

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग

क्रमांक 1171/न.प.766/4/नि-1/72  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 1972.

शासन के वित्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,  
समस्त सभागीय आयुक्त,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
मध्य प्रदेश.

विषय:- त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ वेतन निर्धारण एवं अवकाश प्रयोजनों के लिये दिये जाने बाबत ।

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 65 के नीचे दिये गये जी.आर.ओ. 2 के अनुसार सेवा से त्यागपत्र देने पर, यद्यपि उसके तुरन्त पश्चात पुनर्नियुक्ति हो जाती है, अवकाश के प्रयोजन के लिये पूर्व सेवार्से जप्त हो जाती हैं और पुनर्नियुक्ति पर पूर्व में की गई सेवा के फलस्वरूप अर्जित किया हुआ अवकाश समाप्त हो जाता है। भारत सरकार ने उनके मूलभूत नियम 65 के तहत यह निर्णय लिया है कि, जिन प्रकरणों में त्यागपत्र सिविल सर्विस रेग्युलेशन की धारा 418 (बी) के अधीन होने से त्यागपत्र को त्यागपत्र नहीं माना जाता, ऐसे प्रकरणों में अवकाश कारणों के लिये त्यागपत्र की पूर्व सेवा निरन्तर मानी जावेगी। अतः राज्य शासन ने भी निर्णय लिया है कि ऐसे त्यागपत्र के पूर्व की सेवार्से, जो कि सिविल सर्विस रेग्युलेशन की धारा 418 (बी) के अधीन हो अवकाश कारणों के लिये त्यागपत्र के पूर्व की सेवार्से निरन्तर मानी जावेगी अर्थात् पूर्व में की गई सेवा संबंधी अवकाश का शेष बैलेन्स नई सेवा के हिसाब में जोड़ लिया जावेगा।

2- इसी प्रकार भारत सरकार ने उनके मूलभूत नियम-22 के अधीन यह निर्णय लिया है कि, ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय तैक अपने ही विभाग में अथवा शासन के अधीन अन्य विभागों में किसी पद के लिये योग्य मार्ग द्वारा आवेदन पत्र देते हैं और यदि उनका चयन उस पद के लिये हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से उन्हें अपने पूर्व पद से त्यागपत्र देने के लिये कहा जाय, तो त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ

राज्य शासन के अधीन आने के लिए, यदि नियमों के अन्तर्गत अन्यथा देय हो तो, त्यागपत्र को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए दिया जावे। भारत सरकार द्वारा लिये गये इस नियमों पर विचार कर राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि, राज्य शासन के अधीन आने वाले कर्मचारियों के वेतन और अपने ही अधीन राज्य शासन के अधीन आने वाले विभागों में वेतन के अन्तर्गत माध्यम से, आवेदन पत्र देते हैं और यदि उनका चयन आवेदन पत्र पर ही जम्मा है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से यदि उन्हें अपने पूर्व पद को त्यागपत्र देने को कहा जाता है तो, त्यागपत्र को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए उन्हें पूर्व वेतन का लाभ, अन्यथा नियमों के अन्तर्गत देय हो तो, वेतन निर्धारण के लिये भी अर्थात् आवेदन पत्र प्रकरणों में वेतन, मूलभूत नियम 27 का उपयोग कर, निर्धारित किया जायेगा।

3-

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त क्रम के मामलों में त्यागपत्र मंजूर करने के आदेशों में यह बात स्पष्टतः बताई जानी चाहिए कि कर्मचारी ने अपने नियुक्ति के लिये उचित अनुमति लेकर त्यागपत्र दिया है और उसे त्यागपत्र की मूर्त की सेवाओं का लाभ मिलेगा। इन आदेशों का स्वचरण उपर्युक्त प्रमाणीकरण सहित, संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में सौट किया जाना चाहिए। इसके लिये अलग से मंजूरी जारी करना आवश्यक नहीं है।

4-

इन निर्णयों को मध्यप्रदेश मूलभूत नियमों में सम्मिलित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/—

देवीप्रसाद

उप-सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक आ. 72/स.स. 78574/नि. 1/72 भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 1972

प्रतिलिपि-

- 1. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव मध्यप्रदेश भोपाल,
- 2. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
- 3. निबंधक शासन मुद्रण एवं लेखन कामगरी, मध्यप्रदेश भोपाल,
- 4. राज्य सतर्कता आसक्त, म.प्र. भोपाल,
- 5. पंजीयक, स्थापना अधिकारी/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय भोपाल,
- 6. समस्त वित्तीय अधिकारी/लेखाधिकारी/कोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
- 7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8. सचिव, विधान सभा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9. पंजीयक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

//साक्ष्य प्रतिलिपि//

श्री. बी. श्री वास्तव

हस्ता/ श. मु. पलतले  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग